

::आयुक्त (अपील-11) का कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS-II), CENTRAL EXCISE, 7वीं मंजिल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन,

पोलिटेकनिक के पास,

आम्बवाडी, अहमदाबाद : 380015

7th Floor, Central Excise Building, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad:380015



रजिस्टर	र डाक ए .डी .ट	<u>वारा</u>		/5 /W
क	फाइल संख्या	<u>वारा</u> (File No.) : V2(85)118/Ahd-	-II/Appeals-II/ 2015	-16/26°/65°\
	स्थगन आवेदन	ा संख्या(Stay App. No.):		44 45 40

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): AHM-EXCUS-002-APP- 14-17-18 दिनांक (Date): 21.06.2017 जारी करने की तारीख (Date of issue): श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित Passed by Shri Uma Shanker, Commissioner (Appeals-II)

TT	आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-), अहमदाबाद- ॥, आयुक्तालय द्वारी जीरा
ग	मूल आदेश सं दिनांक से सृजित
	Arising out of Order-In-Original No. <u>Sorad Cracks</u> . Ahmedabad-II issued by: Additional Commissioner Central Excise (Div-), Ahmedabad-II

अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

M/s Yazaki India Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है |

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में प्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए |

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो |

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है |

C. Alo.



(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित की के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:- Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:Under Section 35B/35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं
- the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.
- (ख) उक्तिलिखित पिरच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील. अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पिश्चम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ—20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद—380016.
- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.
- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपन्न इ.ए—3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/— फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम

रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्नत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवांकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवांकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपीलों के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिजार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है .

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

M/s Yazaki India Ltd, A-4, Tata Motors Vendor Park, S. No. 1, North Kotpura, Sanand, Viroch Nagar, Ahmedabad, Gujarat (hereinafter referred to as "the Appellant"), has filed the present appeal against the Order-in-Original No 38/ADC/2015/MKR dated 31.12.2015 (hereinafter referred to as 'impugned orders') passed by the Additional Commissioner of Central Excise, Division-III, Ahmedabad-II, Ahmedabad (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- 2. The facts of the case, in brief, the appellant are register with the Central Excise Department having registration no. AAACT5570FEM007 and engaged in Wiring Harness falling under chapter 85 of Central Excise Traiff Act, 1985. During the course of audit by the internal audit party of the department, it was observed that the appellant is clearing waste & scrap (PVC Copper Wire) generated during the manufacturing of their final product i.e. Wiring Harness. The appellant is not paying any duty on such clearance. On the basis of said information department issued show cause notice demanding duty for such waste & Scrap cleared at the Nil Rate of duty for the period July-2013 to Octomber-2014. The same was adjudicated vide impugned order. The adjudicating authority confirmed the duty of Rs 13,21, 497/-. Penalty under proviso to clause (c) of sub section (1) of present section 11AC of CEA 1944 read with rule 25 of central excise rules, 2002 was also imposed and interest was also demanded.
- 3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant has filed the present appeal on the ground that chargeability of any goods has to satisfy the condition that the activity is manufacturing activity and distinct commodity should come in the existence. The same should be marketable and it should be classified in Central Excise Tariff. They further added that mere change in the definition cannot attract the duty by way of issuing the SCN. They have relied on the Board Instruction in this regard. The appellant further submitted that the adjudicating authority cannot invoke extended period as it is not proposed in the SCN.
- **4.** Personal hearing in the case was granted on 28.02.2017 which was attended by Appellant representative. Written submission was also submitted at the time of personal hearing.
- **5.** I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the appeal, put forth by the appellant. Looking to the facts of the case, I proceed to decide the case on merits.
- on the ground that adjudicating authority while deciding the SCN have not consider the fact that the product generated during the manufacturing is not marketable. Therefore it is not dutiable. The adjudicating authority was in a view that product is classified in the ISRI which can be consider dictionary for all scrap related dispute.



- The product is also specified in CETA. Therefore duty demand is correct.
 - **7.** Now issue to be decided is whether Scrap generated during the manufacturing of Wiring Harness is dutiable or otherwise. If we see the definition of manufacturing activity it is observed that manufacturing mean a new item is emerged and on regular basis.

The said definition was describe in the judgment of constitution bench of Honble Supreme Court of India in the case of Union of India Vs Delhi Cloth and General Mill Co Ltd [1977(1) ELT {J199 (SC)].

Here the PVC insulated Copper Wire used in manufacturing of Wiring Harness and the remaining is small piece of wire which cannot use further. The same is marketable as appellant informed that they are selling it M/s Hamirani Metals Pvt Ltd, Pune for price ragging between 240/- to 260/- per Kg. Further in CETA Chapter head 7404 is for copper waste and scrap. Further as per ISRI Durid is specified for Insulated Copper Wire Scrap. The same is classified in Chapter Head 74040012. Therefore the scrap generated during manufacturing of Wiring Harness is chargeable to duty.

The appellant has relied upon the decision in the case of Finolex Cables Ltd the civil appeal which was dismissed by the Honble Supreme Court of India [2002(146) ELT A100]. It is observed that the said case pertain to Jelly filled Telecommunication Wire whereas the present case pertains to PVC Copper Wire. Since both the commodity is different therefore case law cited by them is not applicable in the present case.

The appellant referred the decision of the larger bench of Honble CESTAT in the case of Hindlaco Industries Ltd Vs CCE Belapur Mumbai-III [2014(308) ELT 472 {Tri-LB}] wherein it is held that following ground should be satisfied for excise goods emerge during the manufacturing process.

- (1) A different commodity in the form of scrap.
- (2) It should be classified in the Central Excise tariff act.
- (3) such scrap is marketable.

In the present case all the three conditions is fulfill. Hence the product emerge in the manufacturing of Wiring Harness is scrap.

In respect of limitation I find that the SRP system was introduce to the trade for their convenience but misuse of the same attract huge penalization. In the present case the contention of the appellant that department cannot invoke extended period as they have reported the same in the ER-1. I find that adjudicating authority in his finding submitted that the Audit was done for the period April-2010 to June-2013 whereas the demand of the duty on scrap is for the period 2011-2015. Further the appellant never reported the clearance of scrap at nil rate of duty by way of note. Therefore in the first SCN the suppression can be invoked. Therefore penalty imposed by adjudicating authority under proviso to clause (c) of sub section (1) of present section 11AC of CEA 1944 read with rule 25 of central excise rules, 2002 is correct. The appeal stands disposed of in above terms.

आयुक्ता

- 8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीलों का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 8. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

2412'1W

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स **- II)** CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

ATTESTED

(S S Chowhan)
SUPERINTENDENT (APPEAL-II),
CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

To, M/s Yazaki India Ltd, A-4, Tata Motors Vendor Park, S. No. 1, North Kotpura, Sanand, Viroch Nagar, Ahmedabad

Copy To:-

- 1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II, Ahmedabad.
- 3. The Dy. /Assistant Commissioner, Central Excise Division-III, Ahmedabad-II, Ahmedabad.
- 4. The Assistant Commissioner(Systems), Central Excise, Ahmedabad-II, Ahmedabad
- 5. Guard File.
- 6. P.A. File.

